

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
राजिन्,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून दिनांक 23 जुलाई, 2007

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 539/ नियोज/प्रशिक्षण/ 2007-08 दिनांक 04.05.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु रूपया 4.80 लाख रुपये (रु० चार लाख अरसी हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत सन्दर्भ में उत्तराखण्ड द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों के उल्लिखित प्राविधानों/मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
- (2) निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व याउचर संख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।
- (3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उन पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का गोलनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक वा.सं. 10-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार कार्यालय उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- (6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय

न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हरत पुरितका तथा बजट गैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हरत पुरितका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि इस मद में गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय विवरण सहित शासन/ महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या -18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-003-प्रशिक्षण -06 - सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान -20- सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

सह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या- 124(P)/वित्त अनुभाग-4/2007 दिनांक 18.07.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(डा0रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या:- 418 (1)/XIV-1/2006तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग गाजरा उत्तराखण्ड देहरादून।।

2. अपर निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

3. परिषद कोषाधिकारी, अल्मोडा।

4. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।

5. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।

6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।